रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251749 CG-DL-E-02022024-251749

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

No. 417]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

का.आ. 445(अ).— केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2653 (2022) और 2699 (2023) के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हैती आदेश, 2023 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएँ (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "आस्ति अवरोधन" से संकल्प 2653 (2022) के पैरा 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा निधियों, अन्य वित्तीय संसाधनों और आर्थिक संसाधनों को रोकना या प्रतिबंधित करना या विनियमित करना अभिप्रेत है:
 - (ख) "शस्त्र प्रतिबंध" से संकल्प 2699 (2023) के पैरा 14 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा छोटे शस्त्रों, हल्के हथियारों और गोला-बारूद की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण को रोकना अभिप्रेत है;

701 GI/2024 (1)

- (ग) "सिमिति" से संकल्प 2653 (2022) के पैरा 19 के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित प्रतिबंध सिमिति अभिप्रेत है:
- (घ) "संकल्प" से 21 अक्टूबर, 2022 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2653 (2022) और माली के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन 2अक्टूबर, 2023 को सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2699 (2023) अभिप्रेत है, जो इस आदेश के साथ क्रमशः उपाबंध I और उपाबंध II के रूप में संलग्न है;
- (ड.) "यात्रा प्रतिबंध" से संकल्प 2653 (2022) के पैरा 3, 4 और 5 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिरोपित यात्रा प्रतिबंध या निर्वंधन अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जाे इस आदेश में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी में परिभाषित हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो ऐसी विधियों में उनके लिए दिए गये हैं।
- 3. व्यक्तियों और अस्तित्वों पर आदेश का लागू होना (1) संकल्प 2653 (2022) और 2699 (2023), जोकि क्रमशः उपाबंध I और उपाबंध II में दिए गए हैं, को इस आदेश का भाग माना जाएगा।
- (2) समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति या संस्थाएं1 अक्टूबर, 2024 तक, संकल्प 2699 (2023) द्वारा विस्तारित किए गए अनुसार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यथाविस्तारित ऐसे ही अन्य आस्ति अवरोधन,शस्त्र प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध के अध्यधीन हैं, अर्थात्:-

सारणी

क. व्यष्टि -

एचटीआई.001 नाम: 1: जिमी 2: चेरीज़ियर 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

शीर्षक: उपलब्ध नहींपदवी: पूर्व पुलिस अधिकारी जन्मतिथि: 30 मार्च 1977 जन्मस्थान: पोर्ट-ऑ-प्रिंस, हैती सुज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं अल्प ज्ञात उर्फ: बारबेक्यू राष्ट्रीयता: हैतियन पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: 001-843-989-7 (एनआईएफ - हैती) पता: 16, इम्प मैनियस, डेल्मास 40 बी, पोर्ट-ऑ-प्रिंस, हैती सूचीबद्ध: 21 अक्टूबर 2022, (तारीख: 20 अक्टूबर 2023 को संशोधित) अन्य जानकारी: जिमी चेरिज़ियर (उर्फ "बारबेक्यू") हैती की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाले कृत्यों में संलिप्त है और उसने ऐसे कृत्यों की योजना बनाई है,उन्हें निर्देशित किया है या ऐसे कृत्य किए हैं जिनसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। जिमी चेरिज़ियर हैती के सबसे दुर्दांत गिरोह नेताओं में से एक है और "जी9 फैमिली और सहयोगी" के रूप में जाने जाने वाले हैती के गिरोह के गठबंधन का सरगना है।

एचटीआई.002 नाम: 1: जॉनसन 2: आंद्रे 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: 5 सेगोंड गिरोह का सरगना जन्मतिथि: 1997 जन्मस्थान: पोर्ट-ऑ-प्रिंस, हैती सुज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहींअल्प ज्ञात उर्फ:इज़ो राष्ट्रीयता: हैती पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता:उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध : 08 दिसंबर 2023 अन्य जानकारी:लिंग: पुरुष

एचटीआई.003 नाम: 1: रेनेल 2: डेस्टिना 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: ग्रैंड रेविन गिरोह का मुख्य सरगना जन्मतिथि: 11 जून 1982 जन्मस्थान: हैती सुज्ञात उर्फ:उपलब्ध नहींअल्प ज्ञात उर्फ:टी लापली राष्ट्रीयता: हैती पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या:उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 08 दिसंबर, 2023 अन्य जानकारी:लिंग: पुरुष

एचटीआई.004 नाम: 1: विल्सन 2: जोसेफ 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: 400 मावोज़ो गिरोह का सरगना जन्मतिथि: 28 फरवरी 1993 जन्मस्थान: हैती सुज्ञात उर्फ:उपलब्ध नहींअल्प ज्ञात उर्फ: लैनमो सैन जू राष्ट्रीयता: हैती पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं पता: उपलब्ध नहीं सूचीबद्ध: 08 दिसंबर 2023 अन्य जानकारी: लिंग: पुरुष

एचटीआई.005 नाम: 1: विटेलहोम 2: इनोसेंट 3: उपलब्ध नहीं 4: उपलब्ध नहीं

पदवी: उपलब्ध नहीं पदनाम: क्रेज़ बैरे गिरोह का सरगना जन्मतिथि: 27 मार्च 1986 जन्मस्थान: पोर्ट-ऑ-प्रिंस, हैतीसुज्ञात उर्फ:उपलब्ध नहीं अल्प ज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता: हैती पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: हैती 004-341-263-3 पता: 64, सोइसन, तबारे 49, पोर्ट-ऑ-प्रिंस, हैती सूचीबद्ध: 08 दिसंबर 2023 अन्य जानकारी: लिंग: पुरुष

ख. इकाई और अन्य समूह, -

[फा. सं. यू.II/152/22/2023] ईनम गंभीर, संयुक्त सचिव

उपाबंध ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2653 (2022)

सुरक्षा परिषद द्वारा 21 अक्टूबर, 2022 को उसकी 9159 वीं बैठक में अंगीकार किया गया

सुरक्षा परिषद

हैती की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए ,

हैती से संबंधित अपने सभी पूर्व के संकल्पों का स्मरण करते हुए, विशेष रूप से इसके संकल्प 2645 (2022), जिसने अन्य बातों के साथ-साथ हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय (बीआईएनयूएच) के जनादेश को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया, ने सामूहिक हिंसा और आपराधिक क्रियाकलाप को तत्काल रोकने की मांग की, और सामूहिक हिंसा, आपराधिक क्रियाकलापों या मानवाधिकारों के हनन में सम्मिलित या समर्थन करने वालों, या अन्यथा हैती और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करने वाली कार्रवाई करने वालों के विरूद्ध, आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने के लिए परिषद की तत्परता व्यक्त की।

हैती में दीर्घ काल से आस्थगित एवं बिगड़ते राजनीतिक, संस्थागत, आर्थिक, सुरक्षा, मानवाधिकार, मानवीय और खाद्य सुरक्षा संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए और हैती के लोगों का समर्थन जारी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए,

यह स्वीकार करते हुए कि बहिष्करण और असमानता हैती से संबंधित स्थिति में गंभीर कारकों के रूप में प्रभाव डालते है, अस्थिरता और असमानता के दीर्घकालिक कारकों का समाधान करने के लिए हैती सरकार की प्राथमिक उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए ,

सुरक्षा स्थितियों तथा संभारतंत्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार और महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी तथा युवाओं, नागरिक समाज एवं अन्य सुसंगत हितधारकों की भागीदारी के साथ, पारदर्शी रीति से आयोजित किए जाने वाले समावेशी, स्वतंत्र और निष्पक्ष विधायी तथा राष्ट्रपति निर्वाचनों के आयोजन की अनुमित देने के लिए हैती के लोगों के नेतृत्व में एक राजनीतिक प्रक्रिया के लिए एक स्थायी, समयबद्ध और सामान्य रूप से स्वीकार्य ढांचे पर तत्काल सहमित पर पहुंचने की आवश्यकता को दोहराते हुए,और राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए हैती सरकार से किए गए अपने अनुरोध को स्मरण करते हुए,

सामूहिक हिंसा और अन्य आपराधिक क्रियाकलापों में अत्यधिक बढ़ोतरी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, जिनमें अपहरण, व्यक्तियों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी, और हत्याएं, तथा बलात्संग एवं यौन दासता सहित यौन और लिंग आधारित हिंसा, साथ ही साथ चल रही अपराधियों के लिए दण्डमुक्ति, भ्रष्टाचार और गिरोहों द्वारा बालकों की भर्ती और इस क्षेत्र के लिए हैती की स्थिति के निहितार्थ सम्मिलत है,

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि सभी प्रकार के हथियारों और उनसे संबंधित सामग्री की अवैध तस्करी तथा व्यपवर्तन विधि के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान से जुड़ी व्यवस्था कमजोर होती है, और इससे मानवीय सहायता के उपबंध में बाधा पहुँंचती है और इसके व्यापक नकारात्मक मानवीय और सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं,

हैती में सामूहिक हिंसा, आपराधिक क्रियाकलापों या मानवाधिकारों के हनन में लगे या समर्थन करने वाले गैर-राज्य संगठनों को छोटे हथियारों, हल्के हथियारों और गोला-बारूद के हस्तांतरण पर रोक लगाने के साथ-साथ उनकी अवैध तस्करी और व्यपवर्तन को रोकने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, अवैध हथियारों की तस्करी और विचलन को रोकने के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें अवैध तस्करी के स्रोतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए समय पर और अद्यतन जानकारी प्रदान करना और आदान-प्रदान करना सम्मिलित है,

हैती में अवैध वित्तीय प्रवाह का समाधान करने की तात्कालिक आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, जो सशस्त्र गिरोहों के संचालन को सक्षम बनाता है और देश की स्थिरता के लिए होने वाले खतरे में बढ़ोतरी करता है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक संगठनों और गिरोहों के बीच संबंधों को तोड़ने को प्राथमिकता देना भी सम्मिलित है,

हैती की नेशनल पुलिस की महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक पहुंच में कमी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, जो बड़े पैमाने पर गिरोहों के नियंत्रण में हैं, और साथ ही गिरोहों द्वारा बंदरगाहों और ईंधन टर्मिनलों पर अवैध कब्जे को रोकने की मांग करते हुए ,

सीमा और बंदरगाहों पर नियंत्रण को बढ़ावा देने, अवैध वित्तीय प्रवाह का पता लगाने, अंतरराष्ट्रीय अपराध, भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं तथा हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए अन्य देशों से सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों की सहायता के लिए ड्रग्स एवं अपराध संंबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा तकनीकी कार्यक्रमों के शुभारंभ का स्वागत करते हुए, जिनमें यूएनओडीसी-विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के हैती में कंटेनर नियंत्रण कार्यक्रम और सीमा प्रबंधन कार्यक्रम सम्मिलित हैं तथा साथ ही आग्नेयास्त्रों की तस्करी से निपटने के लिए कैरेबियन समुदाय (कैरीकॉम) के क्षेत्रीय रोडमैप का स्वागत करते हुए, कैरीकोम जैसे क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए,

हैती में सशस्त्र गिरोहों द्वारा लगातार और अस्थिर करने वाली आपराधिक क्रियाकलापों और गिरोह हिंसा में संलिप्त या सहयोग करने वाले सहभागियों को छोटे तथा हल्के हथियारों और गोला-बारूद के बेरोकटोक हस्तांतरण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए,

संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर हमलों और उनके अपहरण, राजनयिक परिसरों के विरुद्ध हिंसा और मानवीय सहायता को लूटने की निंदा करते हुए और यह स्मरण कराते हुए कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा का प्राथमिक दायित्व मेजबान राष्ट्रका है,

हैती में मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करने के लिए सभी सहभागियों से आह्वान करते हुए और सभी सहभागियों के लिए मानवीय संगठनों द्वारा तत्काल, सुरक्षित और बाधारहित पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए,

इस बात पर जोर देते हुए कि इस संकल्प द्वारा लगाए गए उपायों का उद्देश्य हैती की नागरिक आबादी पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव डालना नहीं है।

यह स्वीकार करते हुए कि इस संकल्प के अनुसार नामित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं को गैरसूचीबद्ध करने के लिए निष्पक्ष और स्पष्ट प्रक्रियाएं मौजूद हैं और ऐसे गैरसूचीबद्ध अनुरोध प्राप्त करने के लिए लोकपाल को अधिकृत करने पर विचार करने के अपने आशय को व्यक्त करते हुए,

यह निश्चित करते हुए कि हैती की स्थिति इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन कार्य करना ,

- 1. जो हिंसा, आपराधिक गतिविधियों और मानवाधिकारों के हनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता है जो हैती और इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करता है, जिसमें अपहरण, यौन और महिलाओं के प्रति हिंसा, मानव तस्करी और प्रवासियों की तस्करी और उनकी हत्याएं, न्यायेतर हत्याएं और सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क द्वारा बालकों की भर्ती सम्मिलित है;
- 2. स्थानीय सुरक्षा स्थिति अनुकूल होते ही समावेशी, स्वतंत्र और निष्पक्ष विधायी और राष्ट्रपित निर्वाचन कराने की अनुमित देने के लिए सभी राजनीतिक सहभागियों से वर्तमान राजनीतिक गितरोध को दूर करने के लिए सार्थक बातचीत में रचनात्मक रूप से सम्मिलित होने का आग्रह करता है;

यात्रा पर प्रतिबंध

3. विनिश्चय करता है कि, इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए, सभी सदस्य देशनिम्नलिखित पैरा 19 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा नामोदिष्ट किसी भी व्यक्ति के अपने भूक्षेत्र में प्रवेश या पारगमन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे परंतु कि वर्तमान पैरा में कुछ भी किसी देश को अपने ही नागरिकों को अपने भूक्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बाध्य नहीं करेगा;

- 4. टिप्पण करता है कि नामोदिष्ट व्यक्तियों के पास कई राष्ट्रीयताएं या पासपोर्ट हो सकते हैं, यह चिंता व्यक्त करता है कि उन दो देशों के बीच यात्रा प्रतिबंध जिनकी एक नामोदिष्ट व्यक्ति की राष्ट्रीयता है यापासपोर्ट है,अनुच्छेद 3 में लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है और अनुरोध करता है कि इस संकल्प के अनुच्छेद 21 में स्थापित विशेषज्ञों पैनल ("विशेषज्ञों पैनल") ऐसी यात्रा के बारे में समिति को जानकारी दे;
- 5. विनिश्चय करता है कि ऊपर पैरा 3 द्वारा लगाए गए उपाय निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे:
 - क. जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित करती है कि ऐसी यात्रा मानवीय आवश्यकता के लिए उचित है जिसमें धार्मिक कार्य सम्मिलित है;
 - ख. जहां न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए प्रवेश या पारगमन आवश्यक है; और
 - ग. जहां समिति मामला-दर-मामला आधार पर यह अवधारित करती है कि छूट से हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा;

आस्तिजब्त

- 6. विनिश्चय करता है कि, इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अविध के लिए, सभी सदस्य देश बिना किसी देरी के अपने भूक्षेत्र में विद्यमान ऐसी सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों को जब्तकरेंगे, जो इस संकल्प के अनुबंध में सूचीबद्ध या सिमित द्वारा नामित किसी भीव्यक्ति या संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में हैं या उनकी ओर से या उनके निर्देश पर किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा, या उनके स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा कार्यरत हैं और आगे यह विनिश्चय करता है कि सभी सदस्य देश यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो ये और न ही कोई अन्य निधि, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को या उनके लाभ के लिए, उनके नागरिकों द्वारा या उनके भूक्षेत्र के भीतर व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए जायें;
- 7. विनिश्चय करता है कि उपरोक्त पैरा 6 द्वारा लगाए गए उपाय उन निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होते हैं जो संबंधित सदस्य देशों द्वारा अवधारित किए गए हैं:
 - क. जो बुनियादी खर्च के लिए आवश्यक है, जिसमें खाद्य पदार्थों, किराया या मोर्गेज, दवाओं और चिकित्सा उपचार, करों, बीमा प्रीमियम और सार्वजनिक उपयोगिता शुल्क का भुगतान या विशेष रूप से उचित पेशेवर शुल्क का भुगतान सम्मिलित है और राष्ट्रीय विधियों के अनुसार विधिक सेवाओं के उपबंध से जुड़े खर्चों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है,राष्ट्रीय विधियों के अनुसार जब्त धन, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों के नियमित रखरखाव के लिए शुल्क या सेवा शुल्क और संबंधित देश द्वारा समिति को अधिकृत करने के आशय की अधिसूचना के पश्चात,जहां उचित हो,ऐसी अधिसूचना के पांच कार्य दिवसों के भीतर समिति द्वारा इंकार न करने स्थिति में ऐसे धन, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच;
 - ख. आवश्यक असाधारण, परंतु कि ऐसा निर्धारण संबंधित देश या सदस्य देशों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया हो और समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो;
 - ग. न्यायिक, प्रशासनिक या मध्यस्थ ग्रहणाधिकार या निर्णय का विषय होना, जिस स्थिति में धन, अन्य वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का उपयोग उस ग्रहणाधिकार या निर्णय को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है, परंतु इसे वर्तमान संकल्प के ग्रहणाधिकार या निर्णय की तारीख से पूर्व दर्ज किया गया हो औरयह सिमिति द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिए नहीं हो और सुसंगत राष्ट्र या सदस्य देशों द्वारा सिमिति को सुचित किया गया हो;
- 8. विनिश्चय करता है कि सदस्य देश उपरोक्त पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार फ्रीज़ खातों में उन खातों पर ऐसे देय ब्याज या अन्य आयको जमा करने की अनुमित दे सकते हैं जोइस संकल्प के उपबंधों के अधीन इन खातों को फ्रीज़ करने की तारीख से पहले देय थे,परंतु ऐसा कोई भी ब्याज, अन्य आय और भुगतान इन उपबंधों के अधीन रहेंगे और फ्रीज़ रहेंगे;
- 9. विनिश्चय करता है कि उपरोक्त पैरा 6 में दिए गए उपाय किसी नामित व्यक्ति या इकाई को ऐसे व्यक्ति या इकाई की सूचीबद्ध से पहले किए गए अनुबंध के अधीन देय भुगतान करने से नहीं रोकेंगे, परंतु सुसंगत देशों ने यह अवधारित

किया हो किउपरोक्त पैरा 6 के अनुसार नामित किसी व्यष्टि या इकाई द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और संबंधित देशों द्वारा समिति को ऐसे भुगतान करने या प्राप्त करने या अधिकृत करने के आशय की अधिसूचना के पश्चात, जहां उचित हो, धन, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को फ्रीज करना या इस प्रयोजन के लिए आर्थिक संसाधन, ऐसे प्राधिकरण से 10 कार्य दिवस पहले भुगतान नहीं किया गया है।;

10. विनिश्चय लेता है कि अन्यत्र संचालित मानवीय सहायता कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संकल्प के पैरा 6 द्वारा लगाए गए उपाय तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशिष्ट अभिकरणों या कार्यक्रमों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले मानवीय संगठन जो मानवीय सहायता प्रदान करते हैं, और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी सिहत उनके कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा हैती में बुनियादी मानव आवश्यकताओं का समर्थन करने वाली अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करते हैं और हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रतिक्रिया योजना में भाग लेने वाले संगठन हैं पर आवश्यक धन, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के भुगतान पर लागू नहीं होंगे;

लक्षित शस्त्र प्रतिबंध

- 11. विनिश्चय करता है कि इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अविध के लिए सभी सदस्य देश सिमित द्वारा नामोदिष्ट व्यष्टि और इकाइयों को या उनके लाभ के लिए अपने क्षेत्रों से या अपने नागरिकों द्वारा या अपने झंडे वाले जहाजों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हथियारों,गोला-बारूद, सैन्य वाहनों और उपकरणों, अर्धसैनिक उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स सिहत सभी प्रकार की संबंधित सामग्री की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए और इससे संबंधित तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय या अन्य सहायता, सैन्य गतिविधियों से संबंधित या किसी हथियार और संबंधित सामग्री के उपबंध, रखरखाव या उपयोग, जिसमें सशस्त्र भाड़े के किमेयों का उपबंध सिम्मिलित है, चाहे वे इनके क्षेत्रों से उत्पन्न हो रहेहैं या नहीं पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएंगे;
- 12. सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों जिनके वे पक्षकार हैं,के अनुसार छोटे और हल्के हथियारों सहित अन्य हथियारों का पता लगाने के लिए पर्याप्त अंकन और रिकॉर्ड रखने के उपाय किए जाएं, और जहां सुसंगत हो, अनुरोध करने पर, पड़ोसी देश को इस संकल्प के पैराग्राफ 11 में लगाए गए उपायों के उल्लंघन में अवैध तस्करी और डायवर्जन को रोकने और पता लगाने में सहायता कैसे की जाएपर विचार किया जाए;
- 13. सभी देशों, विशेष रूप से क्षेत्रीय देशोंसे, अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों सिहत उनके क्षेत्र मेंउनके राष्ट्रीय प्राधिकारियों और विधि के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप, हैती के सभी कार्गो का निरीक्षण करने का आह्वान करता है, यदि संबंधित देश के पास ऐसी जानकारी है जो यह मानने के लिए उचित आधार प्रदान करती है कि कार्गो में ऐसी वस्तुएं सिम्मिलित हैं जिनकी आपूर्ति, बिक्री, स्थानांतरण या निर्यात सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस संकल्प के अनुच्छेद 11 के उपबंधद्वारा निषिद्ध है;
- 14. इस संकल्प के पैरा 11 में अधिरोपित उपायों के उल्लंघन का पता लगाने और इन पर रोक लगाने के लिए, साथ ही निम्नलिखित पैरा 19 के अनुसार स्थापित समिति को उल्लंघन के मामलों की समय पर रिपोर्ट करने के लिए क्षेत्रीय भूमि, वायु और समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित करता है;

प्रतिबंध के लिए मानदंड

- 15. विनिश्चय करते है कि पैरा 3 के उपबंध व्यक्तियों पर लागू होंगे और पैरा 6 तथा11 के उपबंध ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे, जो इस संकल्प के पैरा 19 के अनुसार स्थापित समिति द्वारा ऐसे उपायों के लिए नामोदिष्ट हैं और जो हैती की शांति, सुरक्षा या स्थिरता को खतरे में डालने वाले कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं;
- 16. विनिश्चय लेता है कि ऊपर पैराग्राफ 15 में वर्णित ऐसी कार्रवाइयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु ये ही सीमित नहीं हैं:
 - क. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी आपराधिक क्रियाकलापों को जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं का समर्थन करना, या सिम्मिलित होना और जिसमें ऐसे समूहों और नेटवर्क द्वारा बच्चों की जबरन भर्ती, अपहरण, व्यक्तियों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी,और हत्याएं तथा यौन और महिलाओं के प्रति हिंसा सिम्मिलित है;
 - ख. हथियारों और संबंधित सामग्री की अवैध तस्करी और पथांतर, या उससे संबंधित अवैध वित्तीय प्रवाह का समर्थन करना;

- ग. उपरोक्त उपपैराग्राफ (क) और (ख) में उल्लिखित क्रियाकलाप के संबंध में नामोदिष्ट किसी व्यष्टि या इकाई के लिए या उसकी ओर से या उसके निर्देश पर या अन्यथा का समर्थन करना या वित्तपोषण करना, जिसमें संगठित अपराध से प्राप्त आय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग सम्मिलित है,जिसमें हैती में उत्पन्न होने वाली या उसके माध्यम से पारगमन करने वाली दवाओं और उनके पूर्ववर्तियों के अवैध उत्पादन और तस्करी से प्राप्त आय, व्यक्तियों की तस्करी और हैती से प्रवासियों की तस्करी, या हैती से या वहां से हथियारों की तस्करी सम्मिलित है:
- घ. इस संकल्प के पैराग्राफ 11 में स्थापित हथियार प्रतिबंध के उल्लंघन में कार्य करना, या हैती में सशस्त्र समूहों या आपराधिक नेटवर्क को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री, या स्थानांतरित करना, या हथियार या किसी भी संबंधित सामग्री को हासिल करना, या हैती में सशस्त्र समूहों या आपराधिक नेटवर्क की हिंसक क्रियाकलापों से संबंधित कोई तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण, या वित्तपोषण और वित्तीय सहायता प्रदान करना:
- ड़ हैती में ऐसे कार्यों की योजना बनाना, निर्देशित करना या करना जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का उल्लंघन करते हैं या ऐसे कार्य जो मानवाधिकारों का हनन करते हैं, जिनमें महिलाओं और बालकाें के साथ-साथ न्यायेतर हत्याएं सम्मिलित हैं और हिंसा, अपहरण, जबरन गायब करना, या फिरौती के लिए अपहरण जैसे कृत्य सम्मिलित हैं;
- च. हैती में बलात्संग और यौन दासता सहित यौन और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कृत्यों की योजना बनाना, निर्देशित करना या करना;
- छ. हैती को मानवीय सहायता प्रदान करने में बाधा डालना या हैती में मानवीय सहायता की पहुंच या उसके वितरण में बाधा डालना;
- ज. हैती में संयुक्त राष्ट्र मिशनों और अभियानों के कर्मियों या परिसरों पर हमला करना, ऐसे हमलों के लिए सहायता प्रदान करना;
- 17. मांग करता है कि राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगें कि इस संकल्प को लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए सभी उपाय अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत उनके दायित्वों का अनुपालन करते हों, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि, जो लागू हो, सम्मिलित हैं;
- 18. विनिश्चय करता है कि इस संकल्प के अनुबंध में सूचीबद्ध व्यष्टि ऊपर पैरा 3, 6 और 11 द्वारा अधिरोपित उपायों के अधीन होगा;

प्रतिबंध समिति

- 19. प्रक्रिया के अपने अनंतिम नियमों के नियम 28 के अनुसार, निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए, परिषद के सभी सदस्यों (यहां "समिति") को सम्मिलित करते हुए सुरक्षा परिषद की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया गया है :
 - क. सदस्य देशों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना, सुविधाजनक बनाना और इनमें सुधार करने की दृष्टि से उपरोक्त पैरा 3, 6 और 11 में अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और इस संकल्प के पैरा 5 और 7 में निर्धारित छूट के अनुरोधों पर विचार करना;
 - ख. उन व्यष्टियों और इकाइयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और समीक्षा करना जो उपरोक्त पैरा 15 और 16 में वर्णित कृत्यों में संलिप्त हैं;
 - ग. उपरोक्त पैराग्राफ 3, 6 और 11 में किए गए उपायों के अधीन व्यष्टियों और इकाइयों को नामित करना;
 - घ. ऐसे दिशानिर्देश स्थापित और प्रख्यापित करना जो ऊपर लागू उपायों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हों;
 - ङ. सुरक्षा परिषद को अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ अपने काम पर 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट करना, विशेष रूप से इस संकल्प के पैराग्राफ 3, 6 और 11 द्वारा किए गए उपायों की प्रभावशीलता को मजबूत करने की रीतियों पर और उसके बाद वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करना;

- च. सिमिति और इच्छुक सदस्य राष्ट्रों, विशेष रूप से क्षेत्र के लोगों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, जिसमें उपायों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए सिमिति के साथ बैठक करने के लिए ऐसे राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना सिम्मिलित है:
- छ. लागू उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में सभी राष्ट्रों से वह जानकारी मांगना जो वह उपयोगी समझते हैं;
- ज. पैराग्राफ 3, 6, और 11 में निहित उपायों के कथित उल्लंघन या गैर-अनुपालन के संबंध में जानकारी की जांच करना और उचित कार्रवाई करना:
- 20. सिमिति को अन्य संगत सुरक्षा परिषद प्रतिबंध सिमितियों के साथ सहयोग करने का निर्देश देता है;

रिपोर्ट करना

- 21. महासचिव से अनुरोध करती है कि समिति के परामर्श से 13 महीने की आरंभिक अविध के लिए, समिति के निर्देशन में 4 विशेषज्ञों का एक समूह ("विशेषज्ञों का पैनल") का गठन करें तथा पैनल के कार्य का समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं सुरक्षा व्यवस्था करें, और यह निर्णय लें कि पैनल निम्नलिखित कार्य करेगा:
 - क. इस संकल्प में निर्दिष्ट अपने अधिदेश को पूरा करने में समिति की सहायता करना, जिसमें किसी भी समय समिति को उन व्यक्तियों और संस्थाओं के संभावित रूप से नामित किए जाने से संबंधित जानकारी प्रदान करना सम्मिलित है जो उपर्युक्त पैराग्राफ 15 और 16 में उल्लिखित क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं।
 - ख. इस संकल्प में तय किए गए उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रों, सुसंगत संयुक्त राष्ट्र निकायों, क्षेत्रीय संगठनों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से, विशेष रूप से हैती में हथियारों की तस्करी के स्रोत एवं मार्गों तथा राजनीतिक परिवर्तन को कमजोर करने से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसकी जांच तथा विश्लेषण करना;
 - ग. सिमिति के साथ चर्चा के पश्चात परिषद को 15 मार्च 2023 तक एक अंतरिम रिपोर्ट, 15 सितंबर 2023 से पहले एक अंतिम रिपोर्ट और इसके बीच में आवधिक अपडेट प्रदान करना;
 - घ. इस संकल्प के पैराग्राफ 3, 6 और 11 के अनुसार लागू उपायों के अधीन व्यष्टियों और इकाइयों की सूची पर जानकारी को परिष्कृत और अद्यतन करने में समिति की सहायता करना, जिसमें जानकारी की पहचान करना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचीबद्ध करने के कारण के सारांश हेतु अतिरिक्त जानकारी का उपबंध सम्मिलित है;
- 22. अपनी प्रतिबंध समितियों के कार्य में सहायता के लिए बीआईएनयूएच, यूएनओडीसी, सीएआरआईसीओएम और सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित सुसंगत विशेषज्ञ समूहों के साथ आवश्यकतानुसार सहयोग करने के लिए पैनल को निर्देश देती है:
- 23. सभी पक्षकारों और सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों से विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग सुनिश्चित करने का आग्रह करती है और इसमें सिम्मिलित सभी सदस्य राष्ट्रों से विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सुरक्षा और विशेष रूप से व्यष्टियों, दस्तावेज़ों और साइटों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह करती है जिससे पैनल अपने अधिदेश को क्रियान्वित कर सके;
- 24. यह टिप्पण करती हैं कि पैनल में सम्मिलित होने वाले विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय और महिला/पुरुष प्रतिनिधित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सबसे मजबूत योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी;

पुनर्विलोकन

- 25. यह पृष्टि करती हैं कि यह हैती में स्थिति की निरंतर समीक्षा करेगा और यह इस संकल्प में निहित उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए तैयार रहेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मानकों पर प्राप्त प्रगति को देखते हुए किसी भी समय आवश्यकतानुसार उपायों को मजबूत करना, उसे संशोधित, निलंबित या उन्नत करना सम्मिलित है:
 - क. जब हैती सरकार ने सशस्त्र समूहों और अपराध-संबंधित क्रियाकलापों को संभालने के लिए पर्याप्त न्यायिक और विधि व्यवस्था की क्षमता विकसित कर ली है;अपराध

- ख. सशस्त्र समूहों और आपराधिक नेटवर्क द्वारा इरादतन हत्याओं, अपहरण तथा यौन एवं लिंग-आधारित उत्पीड़न की संख्या सहित अन्य प्रकार की हिंसा की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी, जिसे इस संकल्प के स्वीकार किए जाने के बारह महीने की आरंभिक अवधि से शुरू होकर वार्षिक आधार पर मापा जाता है;
- ग. महासचिव की 13 जून 2022 की रिपोर्ट (एस/2022/481) में उल्लिखित मानक 2, 3, 4 और संबंधित लक्ष्यों पर प्रगति;
- घ. हथियारों की जब्ती की संख्या एवं मात्रा में वृद्धि करके अवैध तस्करी तथा हथियारों की तस्करी की घटनाओं की संख्या और साथ ही उससे होने वाले अवैध वित्तीय लाभ में उत्तरोत्तर कमी, जिसे इस संकल्प के स्वीकार किए जाने के बारह महीने की आरंभिक अवधि से शुरू होकर वार्षिक आधार पर मापा जाता है;
- 26. इस संबंध में महासचिव से विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट समन्वय में, 15 सितंबर 2023 से पहले उपरोक्त पैराग्राफ में स्थापित प्रमुख मानकों पर हुई प्रगति का आकलन करने का अनुरोध करती हैं;
- 27. यूएनओडीसी को बीआईएनयूएच और विशेषज्ञों के पैनल के साथ आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए और हैती में अवैध वित्तीय प्रवाह और तस्करी एवं हथियारों से संबंधित सामग्रियों की तस्करी को रोकने के लिए सिफारिशों पर समिति को रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित करती हैं;
- 28. मामले पर सक्रिय रूप से नजर रखने का विनिश्चय करती हैं।

उपाबंध II

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस/आरईएस/2699 (2023)

सुरक्षा परिषद द्वारा 2 अक्तूबर 2023 को हुई उसकी 9430वीं बैठक में अपनाया गया

सुरक्षा परिषद,

हैती की स्थिति पर अपने सभी पिछले संकल्पों तथा प्रेस वक्तव्यों को याद करते हुए, और संकल्प 2692 (2023) की पुनः पुष्टि करते हुए,

हैती की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए,

इस बात पर जोर देते हुए कि सुरक्षा के उपबंध, विधि व्यवस्था तथा मानवाधिकारों हेतु स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करने और हैती के पूरे क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व हैती सरकार की है, और सशस्त्र समूहों तथा आपराधिक नेटवर्क द्वारा किए जाने वाले हिंसक कृत्यों में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए,

पर्याप्त संख्या, संरचना और उपकरणों वाली एक पेशेवर, आत्मनिर्भर, पूरी तरह से कार्यशील हाईटियन राष्ट्रीय पुलिस, जो पुलिस के पूर्ण स्पेक्ट्रम का संचालन करने में सक्षम है, के महत्व की पुष्टि करते हुए

जो सार्वजिनक सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, लोकतंत्र की मजबूती और हैती की न्याय प्रणाली के पुनरुद्धार और हैती को इन संबंधों में अपनी योजनाओं को सिक्रय रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करें,

बढ़ती हिंसा, आपराधिक क्रियाकलापों और हैती तथा उस क्षेत्र की शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा को कमजोर करने वाले मानवाधिकारों के हनन एवं उल्लंघन,जिसमें अपहरण, यौन और लिंग-आधारित उत्पीड़न, व्यक्तियों की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी, हत्याएं, न्यायेत्तर हत्याएं और साथ ही हथियारों की तस्करी सम्मिलित है,की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए,

हैती में बालकों के विरूद्ध होने वाले उल्लंघनों तथा उत्पीड़न की गंभीरता और संख्या की कड़ी निंदा करते हुए और उसपर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए;और सभी संगठनाें,विशेष रूप से गिरोहों और आपराधिक नेटवर्कों बालकों के विरूद्ध सभी उल्लंघनों और उत्पीड़न, जिनमें हत्या और अपंगता, भर्ती और उपयोग, विशेष रूप से लड़कियों से बलात्संग तथा यौन एवं लिंग-आधारित उत्पीड़न के अन्य प्रकार, स्कूलों तथा अस्पतालों पर हमले, अपहरण, और मानवीय सहायता पहुँचने से इनकार सम्मिलित है, को तुरंत समाप्त करने और रोकने का आग्रह करते हुए,

हाईटियन गिरोहों और उनके समर्थकों सिहत सभी संगठनों से आग्रह करते हुए कि वे अपनी अस्थिर करने वाली और आपराधिक गतिविधियों को बंद करें, और आगे इन गिरोहों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वालों से भी आग्रह करते हुए कि वे स्थानीय बाजारों तक आपूर्ति और पहुंच के लिए आवश्यक सड़कों को अवरुद्ध करने और फसलों और पशुधन, साथ ही चिकित्सा और मानवीय आपूर्ति सहित भोजन के स्रोतों को होने वाले नुकसान को रोकने और हिंसा तथा खाद्य असुरक्षा के बीच संबंध, जो एक असामान्य स्तर पर पहुंच गया है, को उजागर करने के लिए कार्य करें,

हैती और उस क्षेत्र में एक ऐसा सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए जो मानव अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और बालकों की सुरक्षा का सम्मान करता हो, विधि व्यवस्था, राज्य के कार्यात्मक संस्थानों और एक प्रभावी न्यायिक प्रणाली के अनुकूल हो और जीवन-निर्वाही जल, ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति जैसी मानवीय आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता हो,

अपने संकल्प 2653 (2022), जो उच्च स्तर के गिरोह हिंसा और अन्य आपराधिक क्रियाकलापों के साथ-साथ अवैध हथियारों और वित्तीय प्रवाह द्वारा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के प्रतिउत्तर स्थापित प्रतिबंध उपाय है, को याद करते हुए और आगे संकल्प 2664 (2022), जो संकल्प 2653 के पैराग्राफ 10 में निर्धारित परिसंपत्ति फ्रीज अपवाद को प्रतिस्थापित करता है,को पुनः याद करते हुए,

हैती में सुरक्षा और मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, जिसमें हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय (बीआईएनयूएच) को निरंतर सहयोग प्रदान करना भी सम्मिलित है,

इस बात पर जोर देते हुए कि हैती में अस्थिरता के मूल कारणों का समाधान करने के लिए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, और इस संबंध में आवश्यक सुरक्षा परिस्थितियों के पूरा होते ही एक पारदर्शी, समावेशी एवं विश्वसनीय चुनावी प्रक्रियाओं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतांत्रिक संस्थानों को बहाल करने के उद्देश्य से राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा व्यापक संभव आम सहमति बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए,

एक समावेशी अंतर-हाईटियन राष्ट्रीय संवाद के माध्यम से महिलाओं की पूर्ण, समान, सार्थक और सुरक्षित भागीदारी और युवाओं, नागरिक समाज और अन्य सुसंगत हितधारकों की भागीदारी के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष विधायी और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोजित करने की अनुमित देने के लिए हाईटियन के नेतृत्व वाली, हाईटियन के स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बीएनआईयूएच के समर्थन सहित सभी हाईटियन हितधारकों की आवश्यकता को दोहराते हुएऔर आगे सभी हाईटियन हितधारकों से चुनावों के लिए एक स्थायी, समयबद्ध और समान रूप से स्वीकृत प्रक्रिया पर तत्काल एक करार करने का अनुरोध करते हुए,

कैरेबियन समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (सीएआरआईसीओएम) की हैती की हाल की यात्राओं को ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक संवाद का समर्थन करने के लिए इसकी निरंतर प्रतिबद्धता का स्वागत करते हुए,

इस क्षेत्र के देशों के साथ-साथ कैरेबियन समुदाय (सीएआरआईसीओएम) जैसे क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों, विशेष रूप से राजनीतिक संवाद को सुविधाजनक बनाने में सीएआरआईसीओएम और इसके प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विद्यमान राजनीतिक गतिरोध और सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति पर काबू पाने में हैती के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान करते हुए,

उच्च स्तर की सामूहिक हिंसा को संबोधित करने और सुरक्षा को फिर से स्थापित करने के लिए हाईटियन राष्ट्रीय पुलिस के प्रयासों का समर्थन करने हेतु एक विशेष अंतरराष्ट्रीय बल की तैनाती और तकनीकी सहायता के लिए हैती की मंत्रिपरिषद की 6 अक्टूबर 2022 की अपील पर ध्यान देते हुए, आगे महासचिव के तारीख 8 अक्टूबर 2022 (एस/2022/747)के पत्र, महासचिव की तारीख 14 अप्रैल 2023की रिपोर्ट (दस्तावेज़ एस/2023/274), और हाईटियन राष्ट्रीय पुलिस का समर्थन करने के लिए उचित अधिदेश के साथ बहुराष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों को अधिकृत करने के लिए सुरक्षा परिषद के समक्ष 6 जुलाई 2023 को कैरिकॉम की ओर से जमैका के वक्तव्य को ध्यान देते हुए,

हैती में व्यक्तियों के जबरन विस्थापन सहित मानवीय स्थिति की निरंतर और प्रत्यक्ष गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, और सभी पक्षकारों से उल्लंघन एवं दुर्व्यवहार को तुरंत रोकने का आग्रह करते हुए,

गिरोह और सामुदायिक हिंसा को कम करने के साथ-साथ मानवाधिकारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने एवं बाल संरक्षण क्षमता का निर्माण करने के लिए बीआईएनयूएच और यूएनओडीसी के साथ यथोचित समन्वय की आवश्यकता, और आगे राष्ट्रीय पुलिस अधिकारियों की संख्या में विस्तार करने, निरंतर जांच करने, समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग कौशल को बढ़ाने, यौन एवं लिंग-आधारित हिंसा को रोकने और उसपर जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को मजबूत करने, सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण, समान एवं सार्थक भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान, तथा गिरोह-नियंत्रित क्षेत्रों में नष्ट कर दिए गए पुलिस स्टेशनों को बहाल करने सहित सुरक्षा अभियानों के अतिरिक्त राष्ट्रीय

पुलिस की समग्र क्षमताओं का विस्तार करने के लिए बीआईएनयूएच और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा प्रशिक्षण प्रयासों को और मजबृत करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए,

राजनीतिक, संस्थागत और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली गिरोह हिंसा के मूल कारणों को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता (एमएसएस) मिशन के कार्यों के अतिरिक्त व्यापक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, और इस संबंध में, हैती में स्थिरता बहाल होने के बाद भी दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत विकास हेतु सहायता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किए गए आह्वान को दोहराते हुए,

हैती में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के आयोजन सहित लोकतांत्रिक संस्थानों के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के दीर्घकालिक प्रयास में वहाँ लोगों के साथ काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए,

हैती के साथ परामर्श और संकल्प 2692 (2023) में सुरक्षा परिषद द्वारा हैती को सुरक्षा सहायता के सर्वसम्मत रूप से बढ़ाने के बाद,हैती के निमंत्रण पर एक बहुराष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील के उत्तर में केन्या सरकार द्वारा 29 जुलाई की घोषणा का स्वागत करते हुए, और कई सदस्य राष्ट्रों द्वारा सहभागिता के लिए की गई सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हुए,

सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित महासचिव के 26 सितंबर 2023 के पत्र (एस/2023/726) को ध्यान में रखते हुए, अध्याय 7के अधीन सुरक्षा परिषद से प्राधिकार प्राप्त करने की दृढ़ता से इच्छा व्यक्त करता है और जो केन्याई प्रतिनिधिमंडल के मूल्यांकन दौरे के बाद जो आशा व्यक्त करता है कि बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा और हैती की राष्ट्रीय पुलिस के साथ करीबी सहयोग से लिक्षत संचालन करने में सक्षम होगा।

बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन की तैनाती सहित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता के लिए एक सुरक्षित संचालन वातावरण के निर्माण के लिए हैती में हथियारों और गोला-बारूद की अवैध तस्करी को रोकने के महत्व और तात्कालिकता को पहचानते हुए,

21 सितंबर 2023 को केन्या सरकार द्वारा किए गए आह्वान पर ध्यान देते हुए संयुक्त राष्ट्र से हैती की चुनौतियों के लिए समग्र प्रतिक्रिया के भाग के रूप में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता की तैनाती की सुविधा के लिए तत्काल एक उचित रूपरेखा प्रदान करने का आग्रह किया गया, सुरक्षा परिषद से अध्याय 7के अधीन एक संकल्प का अनुमोदन करने का आह्वान करते हुए जो हैती और उसके लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा सहायता मिशन तैयार करती है,

यह निर्धारित करते हुए कि हैती की स्थिति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा बनी हुई है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7के अधीन कार्य करते हुए,

- 1. उन सदस्य राज्यों को अधिकृत करता है जिन्होंने हैती सरकार के साथ सहयोग और समन्वय में, इस संकल्प को अपनाने के बाद बारह महीने की आरंभिक अविध के लिए, जिसका इस संकल्प को अपनाने के नौ महीने बाद समीक्षा किया जाना है, यह मानते हुए कि इस अस्थायी संचालन को लागू करने की लागत स्वैच्छिक योगदान और व्यक्तिगत सदस्य राज्यों और क्षेत्रीय संगठनों के समर्थन से वहन की जाएगी तथा यथालागू अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि सहित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सख्त अनुपालन के साथ हैती में सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल सुरक्षा स्थितियों का निर्माण करने हेतु हैती की राष्ट्रीय पुलिस के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख देश के साथ एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता (एमएसएस) मिशन बनाने और तैनात करने के लिए अपनी भागीदारी के बारे में महासचिव को सुचित किया है, द्वारा
 - (क) हैती की राष्ट्रीय पुलिस को परिचालन सहायता प्रदान करते हुए जिसमें संयुक्त सुरक्षा सहायता संचालन की योजना और संचालन के माध्यम से इसकी क्षमता का निर्माण करना सम्मिलित है, क्योंकि यह हैती में अपहरण, यौन और लिंग आधारित हिंसा, मानवों की तस्करी तथा प्रवासियों और हथियारों की तस्करी, नरसंहार, न्यायेतर हत्याएं, और सशस्त्र समूहों एवं आपराधिक नेटवर्क द्वारा बालकों की भर्ती से संबंधित गिरोहों का मुकाबला करने और सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने के लिए कार्य करता है; तथा
 - (ख) हवाई अड्डे, बंदरगाहों, विद्यालयों, अस्पतालों और प्रमुख चौराहों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना स्थलों एवं पारगमन स्थानों के लिए सुरक्षा के उपबंध के लिए हैती की राष्ट्रीय पुलिस को सहायता प्रदान करते हुए;

- 2. एमएसएस से पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हैती की राष्ट्रीय पुलिस को अपने समर्थन के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली आबादी के लिए मानवीय सहायता तक निर्बाध और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करने का आह्वान करती है:
- 3. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन द्वारा, जैसा कि हैती ने तारीख 22 सितंबर 2023 को अपने पत्र में अनुरोध किया था, हैती की राष्ट्रीय पुलिस के साथ समन्वय में जीवन की हानि को रोकने तथा अपनी क्षमताओं और तैनाती के क्षेत्रों की सीमा के भीतर, असाधारण आधार पर तत्काल अस्थायी उपाय अपनाने जो दायरे में सीमित, समयबद्ध, आनुपातिक और उपरोक्त पैराग्राफ 1 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हों, हैती की राष्ट्रीय पुलिस की यथा आवश्यक गिरफ्तारी और हिरासत सहित बुनियादी विधि तथा व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करने, एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित यथालागू अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन किए जाने का निर्णय लेती है; तथा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व से इस आधार पर अपनाए जाने वाले किसी भी उपाय को सुरक्षा परिषद से अद्यतन करने का अनुरोध करती है;
- 4. सदस्य राज्यों और क्षेत्रीय संगठनों से बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन की तत्काल जरूरतों के आधार पर किमेंयों, उपकरणों और आवश्यक वित्तीय एवं रसद संसाधनों का योगदान करने का आह्वान करता है और योगदान देने वाले सदस्य राज्यों से बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व, सुरक्षा परिषद और महासचिव को मिशन में भाग लेने के लिए उनकी इच्छा के विषय में लिखित रूप में सूचित करने के लिए आमंत्रित करती है तथा हैती और बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व से सुरक्षा परिषद और महासचिव को संबंधित किमेंयों की तैनाती और उपकरण की प्रगति के बारे में नियमित रूप से अद्यतित करने का अनुरोध करती है;
- 5. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि सहित यथालागू सभी अंतरराष्ट्रीय विधियों का सख्ती से पालन करते हुए; हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों को अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करती है,
- 6. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन से अपने अधिदेश में संचालन की सभी योजना और आचरण में बाल संरक्षण और अन्य कमजोर समूहों की सुरक्षा को एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में ध्यान में रखने का अनुरोध करती है;
- 7. हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों से गिरोह-विरोधी अभियानों, समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग, बालकों और महिलाओं की सुरक्षा, और पीड़ित-केंद्रित । रूप में यौन और लिंग-आधारित हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने में पूर्ण विशेषज्ञता को सिम्मिलित करने तथा उचित आचरण और अनुशासन सुनिश्चित करने एवं यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने जिसमें सभी कर्मियों और अन्य सुरक्षित भर्ती प्रक्रियाओं की जांच करना, एमएसएस के सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करते हुए, मानवाधिकारों, बाल संरक्षण, और यौन एवं लिंग आधारित हिंसा पर पूर्व-तैनाती और मिशन प्रेरित जागरूकता प्रशिक्षण सिम्मिलित है तथा घटनाओं के घटित होने पर उनका पता लगाने और उनके कर्मियों से जुड़े ऐसे आचरण के मामलों में एक सुरक्षित उत्तरजीवी और पीड़ित- केंद्रित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिसमें सुरक्षित और सुलभ शिकायत तंत्र प्रदान करना और कदाचार के सभी आरोपों की समय पर जांच करना, अपराधियों को जिम्मेदार ठहराना तथा उन इकाइयों द्वारा व्यापक या प्रणालीगत यौन शोषण और दुर्व्यवहार सहित कदाचार के विश्वसनीय सबूत होने पर इकाइयों को वापस भेजने का अनुरोध करती है:
- 8. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व से परिषद को, हैती सरकार और एमएसएस में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों के समन्वय में, मिशन की पूर्ण तैनाती से पहले, लेकिन जो केवल हैती सरकार और एमएसएस में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों के साथ परामर्श और सहयोग से विकसित संचालन की अवधारणा तक सीमित न हो, सहित तैनाती का क्रम, मिशन के लक्ष्यों और अंतिम स्थिति, संबंध के नियम, साथ ही संभावित वित्तीय आवश्यकताएं जिन्हें स्वैच्छिक अंशदानों द्वारा वित्त पोषित किया जाना है और तैनात किये जाने वाले किम्यों की संख्या पर सूचित करने का अनुरोध करती है;
- 9. संबंध के नियम और हैती और एमएसएस में भाग लेने वाले अन्य सदस्य राज्यों के परामर्श से बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व में बल के उपयोग पर किसी भी निर्देश को विकसित किया जाना चाहिए और हैती की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि सहित यथालागू, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सख्ती से अनुपालन किए जाने की पुष्टि करती है;
- 10. हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों से हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन की रूपरेखा में काम करने वाली अपनी टुकड़ियों के लिए पारदर्शिता, आचरण और अनुशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने, हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन या दुरुपयोग को रोकने,

जांच करने, संबोधित करने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिए एक सशक्त अनुपालन तंत्र स्थापित करने का अनुरोध करती है;

- 11. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन से मानव अधिकारों के उल्लंघन या दुरुपयोग, विशेष रूप से यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने के साथ ही तैनाती के दौरान संचालनों की योजना और परिचालन लागू अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार होगा, यह सुनिश्चित करने का आह्वान करती है;
- 12. हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में भाग लेने वाले सदस्य राज्यों से विश्व स्वास्थ्य संगठन के जल गुणवत्ता: दिशानिर्देशों, मानकों और 2001 से पानी से संबंधित संक्रामक रोगों के लिए खतरे के आकलन और खतरा प्रबंधन पर स्वास्थ्य प्रकाशन, तथा हैती के अधिकारियों के सहयोग से, जो जल-जिनत बीमारी से बचाव के लिए साझा उत्तरदायित्व निभाते हैं; के अनुसार जल-जिनत बीमारियों के परिचय और प्रसार से बचाव के लिए उचित अपिशष्ट जल प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय नियंत्रण अपनाने का अनुरोध करती है;
- 13. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन से यूएनओडीसी और मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय सिहत लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित न होकर, बीआईएनयूएच और संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के साथ सहयोग करने, हैती में सुरक्षा को फिर से स्थापित करने के लिए हैती की राष्ट्रीय पुलिस के प्रयासों का समर्थन करने जिसमें हथियारों और संबंधित सामग्रियों की अवैध तस्करी एवं व्यपवर्तन से निपटने तथा सीमाओं और बंदरगाहों के प्रबंधन और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए हैती की राष्ट्रीय पुलिस के प्रयास सम्मिलित हैं; का अनुरोध करती है।
- 14. विनिश्चय करती है कि संकल्प 2653 (2022) के पैराग्राफ 11 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 "यह विनिश्चय करती है कि, इस संकल्प को अपनाने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए, सभी
 सदस्य राज्य अपने क्षेत्रों से या उनके नागरिकों के माध्यम से या उनके झंडे वाले जहाजों या छोटे अस्त्रों, हल्के
 हथियारों और गोला-बारूद के विमानों के उपयोग से हैती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण को
 रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे तथा इसके अतिरिक्त यह विनिश्चय करती है कि यह उपाय इन पर लागू नहीं
 होंगे:
 - क. संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र-अधिकृत मिशन या हैती सरकार की कमान के अधीन कार्य करने वाली एक सुरक्षा इकाई को छोटे अस्त्रों, हल्के हथियारों या गोला-बारूद की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण, जिसका उपयोग उन संस्थाओं द्वारा या उन संस्थाओं के साथ समन्वय में किया जाना है और उनका उद्देश्य पूरी तरह से हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है:
 - ख. हैती में शांति और स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प 2653 (2022) के अनुसार स्थापित समिति द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित हैती को छोटे अस्त्रों, हल्के हथियारों और गोला-बारूद की अन्य आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण;"
- 15. हैती में सभी पक्षों से अपने अधिदेश के कार्यान्वयन में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के साथ पूर्ण सहयोग करने और बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन की सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान करती है;
- 16. महासचिव से अनुरोध करती है कि एक न्यास कोष को एक तंत्र के रूप में स्थापित किया जाए जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में स्वैच्छिक अंशदानों की सुविधा प्रदान कर सके जिससे अधिदेश को सक्षम और क्रियान्वित किया जा सके:
- 17. पृष्टि करती है कि एमएसएस और एमएसएस दाताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव एमएसएस को संभार तंत्रीय सहायता पैकेज प्रदान कर सकते हैं, जो उपलब्ध स्वैच्छिक अंशदानों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण वित्तीय प्रतिपूर्ति और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी (एचआरडीडीपी) के पूर्ण सम्मान के अधीन है;
- 18. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेताओं से पारदर्शिता और आचरण के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने, और संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में, महासचिव के माध्यम से सुरक्षा परिषद को नियमित रिपोर्टिंग के एक भाग के रूप में एमएसएस का वास्तविक कार्यसंचालन शुरू होने के बाद हर तीन महीने में रिपोर्ट करने का अनुरोध करते हुए, जिनमें मिशन के संघटन, उचित आचरण और अनुशासन सुनिश्चित करना और यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को रोकना; और कदाचार एवं अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करने के उपाय, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सम्मिलित हैं;
- 19. महासचिव से सुरक्षा परिषद को महासचिव की नियमित रिपोर्टिंग के भाग के रूप में, इस संकल्प को अपनाने के नौ महीने के भीतर, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के अधिदेश के संभावित अनुकूलन या इसके परिवर्तन पर आवश्यकतानुसार सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध करती है;

- 20. बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन के नेतृत्व से मिशन के समापन और वापसी के लिए एक रणनीति विकसित करने तथा सुरक्षा परिषद को नियमित रिपोर्टिंग में उस मामले पर जानकारी सम्मिलत करने का अनुरोध करती है:
- 21. विशेष रूप से लंबे समय के लिए हैती के संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र के अंगों, निकायों और अभिकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सिहत अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि स्थिरता प्राप्त की जा सके और बनाए रखी जा सके तथा गरीबी से निपटा जा सके;
- 22. हैती के अधिकारियों और अन्य हितधारकों से दृढ़तापूर्वक यथाशीघ्र व्यापक संभावी सहमति के लिए समझौते करने के लिए सीएआरआईसीओएम और बीआईएनयूएच के अच्छे कार्यालयों के साथ पूरा सहयोग करने का आग्रह करती है;
- 23. मामले पर सक्रिय रूप से नजर रखने का विनिश्चय करती है।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2024

- **S.O. 445(E).** In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following order to implement the Resolutions 2653 (2022) and 2699 (2023) of the United Nations Security Council adopted under the Chapter VII of the Charter of the United Nations, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Haiti order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In this order, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "asset Freeze" means freezing or restricting or regulating the funds, other financial resources and economic resources by the Central Government pursuant to paragraphs 6, 7, 8, 9 and 10 of the Resolution 2653 (2022);
 - (b) "arms Embargo" means preventing direct or indirect supply, sale or transfer of small arms, light weapons and ammunition by the Central Government pursuant to paragraph 14 of the Resolution 2699 (2023);
 - (c) "Committee" means the Sanctions Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 19 of the Resolution 2653 (2022);
 - (d) "Resolution" means the Resolution 2653 (2022) of the Security Council of the United Nations adopted on the 21st October, 2022 and Resolution 2699 (2023) adopted by the Security Council on the 2nd October, 2023 under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Mali appended to this order as Annexure I and Annexure II, respectively;
 - (e) "travel Ban" means travel ban or restrictions as imposed by the Central Government pursuant to paragraphs 3, 4 and 5 of the Resolution 2653 (2022).
- (2) Words and expressions used but not defined in this order and defined in any other law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.
- 3. Application of order to individuals and entities.— (1) The Resolutions 2653 (2022) and 2699 (2023), which are at Annexure I and Annexure II, respectively, shall be considered as part of this order.
- (2) The following individuals or entities designated by the Committee are subject to asset freeze, arms embargo and travel ban until the 1st October, 2024 as extended by the Resolution 2699 (2023) or until such other time as may be extended by the United Nations Security Council, namely: –

TABLE

A. Individuals.-

HTi.001 Name: 1: JIMMY 2: CHERIZIER 3: na 4: na

Title: na **Designation**: Former Police Officer **DOB**: 30 March 1977 **POB**: Port-au-Prince, Haiti Good quality **a.k.a.**: na Low quality **a.k.a.**: BARBEQUE **Nationality**: Haitian Passport **no**: na National identification **no**: 001-843-989-7 (NIF – Haiti) **Address**: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haiti Listed **on**: 21 Oct. 2022, (amended on: 20 Oct. 2023) Other **information**: Jimmy Cherizier (AKA "Barbeque") has engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Haiti and has planned, directed, or committed acts that constitute serious human rights abuses. Jimmy Cherizier is one of Haiti's most influential gang leaders and leads an alliance of Haitian gangs known as the "G9 Family and Allies".

HTi.002 Name: 1: JOHNSON 2: ANDRE 3: na 4: na

Title: na **Designation:** Leader of 5 Segond gang **DOB:**1997 **POB:** Port-au-Prince, Haiti Good quality **a.k.a.:** na Low quality **a.k.a.:** Izo Nationality: Haiti Passport **no:** na National identification **no:** na **Address:** na Listed on: 08 Dec. 2023Other information: Gender: Male

HTi.003 Name: 1: RENEL2: DESTINA 3:na 4: na

Title: na **Designation:** Main leader of Grand Ravine gang **DOB:** 11 Jun. 1982**POB:** Haiti Good quality **a.k.a.:** naLow quality **a.k.a.:** Ti Lapli **Nationality:** Haiti Passport **no:** naNational identification **no:** na **Address:** na Listed **on:** 08

Dec. 2023Other information: Gender: Male

HTi.004 Name: 1: WILSON2: JOSEPH 3: na 4: na

Title: na **Designation:** Leader of 400 Mawozo gang **DOB:** 28 Feb. 1993 **POB:** HaitiGood quality **a.k.a.**: naLow quality **a.k.a.**: Lanmo San Jou **Nationality:** Haiti Passport **no:** na National identification **no:** na **Address:** na Listed **on:** 08 Dec. 2023Other **information:** Gender: Male

HTi.005 Name: 1: VITELHOMME2: INNOCENT 3: na 4: na

Title: NA Designation: Leader of Kraze Barye gang. DOB: 27 Mar. 1986 POB: Port-au-Prince, Haiti Good quality a.k.a.: NALow quality a.k.a.: NA Nationality: Haiti Passport no: NANational identification no: Haiti004-341-263-3Address: 64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti Listed on: 08 Dec. 2023 Other information: Gender: Male

B. Entities and other groups.-

[F. No. U.II/152/22/2023]

EENAM GAMBHIR, Jt. Secy.

Annexure I

United Nations Security Council Resolution S/RES/2653 (2022)

Adopted by the Security Council at its 9159th meeting, on 21 October, 2022

The Security Council,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Haiti,

Recalling all its previous resolutions on Haiti, in particular its resolution 2645 (2022), which inter alia extended the mandate of the United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH) for one year, demanded an immediate cessation of gang violence and criminal activity, and expressed the Council's readiness to take appropriate measures, as necessary, against those engaged in or supporting gang violence, criminal activities or human rights abuses, or who otherwise take action that undermines the peace, stability, and security of Haiti and the region,

Noting with deep concern the protracted and deteriorating political, institutional, economic, security, human rights, humanitarian and food security crises in Haiti and reaffirming the commitment of the international community to continue to support the people of Haiti,

Recognizing that exclusion and inequality have an impact as aggravating factors in the situation concerning Haiti,

Stressing the primary responsibility of the Government of Haiti to address longstanding drivers of instability and inequality,

Reiterating the need to reach an urgent agreement on a sustainable, time-bound and commonly accepted framework for a political process led by Haitians to permit the organization of inclusive, free and fair legislative and presidential elections, carried out in a transparent manner, as soon as security conditions and logistical preparations permit, and with the full, equal and meaningful participation of women and the engagement of youth, civil society, and other relevant stakeholders, and recalling its request to the Government of Haiti to provide an update on the political process,

Expressing grave concern about the extremely high levels of gang violence and other criminal activities, including kidnappings, trafficking in persons and the smuggling of migrants, and homicides, and sexual and gender-based violence including rape and sexual slavery, as well as ongoing impunity for perpetrators, corruption and recruitment of children by gangs and the implications of Haiti's situation for the region,

Concerned that illicit trafficking and diversion of arms and related materiel of all types contributes to undermining the rule of law and respect for human rights, and can impede the provision of humanitarian assistance and have wide ranging negative humanitarian and socioeconomic consequences,

Noting the need to prohibit the transfer of small arms, light weapons, and ammunition to non-state actors engaged in or supporting gang violence, criminal activities, or human rights abuses in Haiti, as well as to prevent their illicit trafficking and diversion,

Encouraging cooperation between Member States to prevent illicit arms trafficking and diversion, including through providing and exchanging timely and up to date information in order to identify and combat illicit trafficking sources and supply chains,

Acknowledging the urgent need to address the illicit financial flows to Haiti enabling armed gangs to operate and posing a growing threat to the country's stability, including by prioritizing breaking links between political and economic actors and gangs,

Expressing concerns about the Haitian National Police's lack of access to vital ports which are largely under the control of gangs, and further demanding to stop the illegal occupation of ports and fuel terminals by gangs,

Welcoming the launch of technical programmes by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) to assist national authorities to promote border and ports control, trace illicit financial flows, collaborate across borders to combat transnational crime, corruption, and drug and arms trafficking, including through the UNODC-World Customs Organization (WCO) Container Control Programme in Haiti and border management programmes, and further welcoming the Caribbean Community's (CARICOM) regional roadmap to combat the trafficking of firearms,

Recognizing the important role of neighboring countries, regional and subregional organizations such as CARICOM, and other international partners,

Expressing deep concern at the persistent and destabilizing criminal activities perpetrated by armed gangs in Haiti and the unabated transfer of small arms, light weapons, and ammunition to actors engaged in or supporting gang violence,

Condemning attacks and kidnappings of UN personnel, violence against diplomatic premises, and the looting of humanitarian aid, and recalling that the primary responsibility for the safety and security of United Nations personnel and assets rests with the host state,

Calling upon all actors in Haiti to issue clear orders prohibiting all human rights violations and abuses, and underscoring the necessity for all actors to ensure immediate, safe and unhindered access by humanitarian organizations,

Stressing that the measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of Haiti,

Recognizing the need to ensure that fair and clear procedures exist for delisting individuals, groups, undertakings, and entities designated pursuant to this resolution and expressing its intent to consider authorizing the Ombudsperson to receive such delisting requests,

Determining that the situation in Haiti continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

- 1. Demands an immediate cessation of violence, criminal activities, and human rights abuses which undermine the peace, stability and security of Haiti and the region, including kidnappings, sexual and gender-based violence, trafficking in persons and the smuggling of migrants, and homicides, extrajudicial killings and recruitment of children by armed groups and criminal networks;
- 2. Urges all political actors to constructively engage in meaningful negotiations to overcome the current political stalemate in order to allow the holding of inclusive, free and fair legislative and presidential elections, as soon as the local security situation permits;

Travel Ban

- 3. Decides that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of any individuals designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 below, provided that nothing in the present paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;
- 4. Notes that designated individuals may have multiple nationalities or passports, expresses its concern that travel between the two States of which a designated individual has nationality or
- a passport may undermine the objectives of the travel ban imposed in paragraph 3, and requests that the Panel of Experts established in paragraph 21 of this resolution (the "Panel of Experts") report to the Committee information about such travel;
- 5. Decides that the measures imposed by paragraph 3 above shall not apply:

- a. Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;
- b. Where entry or transit is necessary for the fulfillment of a judicial process; and
- c. Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and stability in Haiti;

Asset Freeze

- 6. Decides that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by any individuals or entities listed in the Annex to this resolution or designated by the Committee, or by any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that neither these nor any other funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly, to or for such individuals' or entities' benefit, by their nationals or by persons within their territory;
- 7. Decides that the measures imposed by paragraph 6 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:
 - a. To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;
 - b. To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee;
 - c. To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;
- 8. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 6 above of interests or other earnings due on those accounts or any payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continues to be subject to these provisions and are frozen:
- 9. Decides that the measures in paragraph 6 above shall not prevent a designated individual or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such an individual or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by an individual or entity designated pursuant to paragraph 6 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;
- 10. Decides that without prejudice to humanitarian assistance programmes conducted elsewhere, the measures imposed by paragraph 6 of this resolution shall not apply to the payment of funds, other financial assets or economic resources necessary to ensure the timely delivery of urgently needed humanitarian assistance or to support other activities that support basic human needs in Haiti, by the United Nations, its specialised agencies or programmes, humanitarian organisations having observer status with the United Nations General Assembly that provide humanitarian assistance, and their implementing partners including bilaterally or multilaterally funded non-governmental organisations participating in the United Nations Humanitarian Response Plan for Haiti;

Targeted Arms Embargo

11. Decides that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to, or for the benefit of, the individuals and entities designated by the Committee from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial or other assistance, related to military activities or the provision, maintenance

or use of any arms and related materiel, including the provision of armed mercenary personnel whether or not originating in their territories;

- 12. Encourages Member States to ensure adequate marking and recordkeeping measures are in place to trace arms, including small arms and light weapons, in accordance with the international and regional instruments to which they are parties, and to consider how best to assist, where relevant and upon their request, neighboring countries in preventing and detecting illicit trafficking and diversion in violation of measures imposed in paragraph 11 of this resolution:
- 13. Calls upon all States, in particular regional countries, to inspect, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to Haiti in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 11 of this resolution for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;
- 14. Encourages regional land, air, and maritime cooperation, as applicable, to detect and prevent violations of measures imposed in paragraph 11 of this resolution, as well as to report cases of violations in a timely manner to the Committee established pursuant to paragraph 19 below;

Sanctions Designation Criteria

- 15. Decides that the provisions of paragraph 3 shall apply to individuals, and that the provisions of paragraphs 6 and 11 shall apply to individuals and entities, as designated for such measures by the Committee established pursuant to paragraph 19 of this resolution, as responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions that threaten the peace, security or stability of Haiti;
- 16. Decides that such actions as described in paragraph 15 above include, but are not limited to:
 - Engaging in, directly or indirectly, or supporting criminal activities and violence involving armed groups and criminal networks that promote violence, including forcible recruitment of children by such groups and networks, kidnappings, trafficking in persons and the smuggling of migrants, and homicides and sexual and gender-based violence;
 - b. Supporting illicit trafficking and diversion of arms and related materiel, or illicit financial flows related thereto:
 - c. Acting for or on behalf of or at the direction of or otherwise supporting or financing an individual or entity designated in connection with the activity described in subparagraphs (a) and (b) above, including through the direct or indirect use of the proceeds from organized crime, including proceeds from illicit production and trafficking in drugs and their precursors originating in or transiting through Haiti, the trafficking in persons and the smuggling of migrants from Haiti, or the smuggling and trafficking of arms to or from Haiti;
 - d. Acting in violation of the arms embargo established in paragraph 11 of this resolution, or as having directly or indirectly supplied, sold, or transferred to armed groups or criminal networks in Haiti, or as having been the recipient of, arms or any related materiel, or any technical advice, training, or assistance, including financing and financial assistance, related to violent activities of armed groups or criminal networks in Haiti;
 - e. Planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or acts that constitute human rights abuses, including those involving extrajudicial killing, including of women and children, and the commission of acts of violence, abduction, enforced disappearances, or kidnappings for ransom in Haiti;
 - f. Planning, directing or committing acts involving sexual and gender-based violence, including rape and sexual slavery, in Haiti;
 - g. Obstructing delivery of humanitarian assistance to Haiti or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Haiti;
 - h. Attacking personnel or premises of United Nations missions and operations in Haiti, providing support for such attacks;
- 17. Demands that States ensure that all measures taken by them to implement this resolution comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, international human rights law and international refugee law, as applicable;
- 18. Decides that the individual listed in the annex of this resolution shall be subject to the measures imposed by paragraphs 3, 6 and 11 above;

Sanctions Committee

- 19. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake the following tasks:
 - a. To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 3, 6, and 11 above with a view to strengthening, facilitating and improving implementation of these measures by Member States, and to consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraph 5 and 7 of this resolution;
 - b. To seek and review information regarding those individuals and entities who may be engaging in the acts described in paragraph 15 and 16 above;
 - c. To designate individuals and entities to be subject to the measures imposed in paragraphs 3, 6, and 11 above;
 - d. To establish and promulgate such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;
 - e. To report within 60 days to the Security Council on its work with its observations and recommendations, in particular on ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraphs 3, 6, and 11 of this resolution and thereafter to report on an annual basis;
 - f. To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;
 - g. To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed;
 - h. To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in paragraphs 3, 6, and 11;
- 20. Directs the Committee to cooperate with other relevant Security Council Sanctions Committees;

Reporting

- 21. Requests the Secretary-General to create for an initial period of 13 months, in consultation with the Committee, a group of 4 experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee and to make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel, and decides that the Panel shall carry out the following tasks:
 - a. Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution, including through providing the Committee at any time with information relevant to the potential designation at a later stage of individuals and entities who may be engaging in the activities described in paragraphs 15 and 16 above;
 - b. Gather, examine and analyze information from States, relevant UN bodies, regional organizations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents regarding the source and routes of arms trafficking to Haiti and incidents of undermining the political transition;
 - c. Provide to the Council, after discussion with the Committee, an interim report by 15 March 2023, a final report no later than 15 September 2023, and periodic updates in between;
 - d. To assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals and entities subject to measures imposed pursuant to paragraphs 3, 6, and 11 of this resolution, including through the provision of identifying information and additional information for the publicly available narrative summary of reasons for listing;
- 22. Directs the Panel to cooperate with BINUH, the UNODC, CARICOM and relevant expert groups established by the Security Council to support the work of its Sanctions Committees, as appropriate;
- 23. Urges all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of Experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel to execute its mandate;
- 24. Notes that the selection process of the experts composing the Panel should prioritize appointing individuals with the strongest qualifications to fulfil the duties described above while paying due regard to the importance of regional and gender representation in the recruitment process;

Review

- 25. Affirms that it shall keep the situation in Haiti under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of progress achieved on the following key benchmarks:
 - a. When the Government of Haiti has developed adequate judicial and rule of law capacity to handle armed groups and criminal-related activities;
 - b. Progressive reduction in the amount of violence committed by armed groups and criminal networks, including the number of intentional homicides, kidnappings and incidents of sexual and gender-based violence, as measured on an annual basis, beginning over the initial period of twelve months from adoption of this resolution;
 - c. Progress on benchmarks 2, 3, 4, and related targets as outlined in the Secretary-General's report of 13 June 2022 (S/2022/481);
 - d. Progressive decrease in the number of incidents of illicit trafficking and diversion of arms, as well as illicit financial flows there from, including by increasing the number and volume of arms seizures, as measured on an annual basis, beginning over the initial period of twelve months from adoption of this resolution;
- 26. Requests in this regard the Secretary-General, in close coordination with the Panel of Experts, to conduct, no later than 15 September 2023, an assessment of progress achieved on the key benchmarks established in the paragraph above:
- 27. Invites the UNODC to work with BINUH and the Panel of Experts, as appropriate, and to report to the Committee on recommendations to stem illicit financial flows and trafficking and diversion of arms related materiel in Haiti:
- 28. Decides to remain actively seized of the matter.

Annexure II

United Nations Security Council Resolution S/RES/2699 (2023)

Adopted by the Security Council at its 9430th meeting, on 2 October, 2023

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions and press statements, and reaffirming resolution 2692 (2023), on the situation in Haiti,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Haiti,

Emphasizing that the Government of Haiti has the primary responsibility for the provision of security, ensuring stability and respect for the rule of law and human rights, and for the protection of civilians across the territory of Haiti, and expressing great concern at the increasingly violent actions taken by armed groups and criminal networks,

Reaffirming the importance of a professional, self-sustaining, fully functioning Haitian National Police of adequate size, structure and equipment, able to conduct the full spectrum of police functions, for the maintenance of public safety, respect for human rights, consolidation of democracy and the revitalization of Haiti's system of justice and encouraging Haiti to pursue actively its plans in these respects,

Condemning in the strongest terms the increasing violence, criminal activities, and human rights abuses and violations which undermine the peace, stability, and security of Haiti and the region, including kidnappings, sexual and gender-based violence, trafficking in persons and the smuggling of migrants, homicides, extrajudicial killings, as well as arms smuggling,

Strongly condemning and expressing deep concern over the gravity and numbers of violations and abuses committed against children in Haiti; and urging all actors, especially gangs and criminal networks, to immediately end and prevent all violations and abuses against children, including those involving killing and maiming, recruitment and use, rape and other forms of sexual and gender-based violence, particularly against girls, attacks on schools and hospitals, abduction, and denial of humanitarian access,

Urging all actors, including Haitian gangs and their supporters, to cease their destabilizing and criminal activities, and further urging those with the ability to influence the gangs to act to stop the blocking of roads required for the supplying of and access to local markets and the damaging of sources of food, including crops and livestock, as well

as medical, and humanitarian supplies, and highlighting the link between violence and food insecurity, that has reached unprecedented levels,

Stressing the need to create a safe and secure environment in Haiti and the region that enables respect for human rights, in particular women's rights, and the protection of children, is conducive to the rule of law, functional state institutions and an effective judicial system, and facilitates the humanitarian delivery of life -sustaining water, fuel, food, and medical supplies,

Recalling its resolution 2653 (2022), which established sanctions measures in response to the threat to international peace and security in the region posed by the high levels of gang violence and other criminal activities, as well as of illicit arms and financial flows, and further recalling resolution 2664 (2022) which supersedes the asset freeze exception set forth in paragraph 10 of resolution 2653,

Reaffirming the commitment of the international community to address the security and humanitarian needs in Haiti, including through offering continued support to the United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH),

Stressing that addressing the root causes of instability in Haiti requires political solutions, and in this regard further emphasizing the urgent need to encourage wider participation and forge the broadest possible consensus in the political process, with, as soon as necessary security conditions are met, a view to holding transparent, inclusive, and credible electoral processes and free and fair elections, and restoring democratic institutions,

Reiterating the need for all Haitian stakeholders, including with BINUH's support, to continue to facilitate a Haitian-led, Haitian-owned political process to permit the organization of free and fair legislative and presidential elections, with the full, equal, meaningful, and safe participation of women and the engagement of youth, civil society, and other relevant stakeholders through an inclusive inter-Haitian national dialogue, and further requests all Haitian stakeholders to urgently reach an agreement on a sustainable, time-bound and commonly accepted roadmap for elections,

Taking note of the recent visits by the Eminent Persons Group of Caribbean Community (CARICOM) to Haiti and welcoming its continued commitment to supporting the political dialogue,

Recognizing the key role of countries in the region, as well as regional and subregional organizations such as the Caribbean Community (CARICOM), and other international partners, in particular the key role of CARICOM and its Eminent Persons Group in facilitating the political dialogue, and calling on the international community to remain committed to Haiti's efforts in overcoming the ongoing political stalemate and security and humanitarian situation,

Taking note of the direct appeal of 6 October 2022 of Haiti's Council of Ministers for the deployment of a specialized international force and technical assistance to support the Haitian National Police's efforts to address high levels of gang violence and re-establish security, further taking note of the letter dated 8 October 2022 of the Secretary-General (S/2022/747), the report of the Secretary-General (document S/2023/274) dated 14 April 2023, and Jamaican statement on behalf of CARICOM before the Security Council on 6 July 2023 to authorize multinational security efforts with the appropriate mandate to support the Haitian National Police,

Gravely concerned by the continued and significant deterioration of the humanitarian situation in Haiti, including the forced displacement of persons, and urging all parties to immediately cease violations and abuses,

Taking note of the need to coordinate, as appropriate, with BINUH and UNODC to reduce gang and community violence, as well as to ensure respect for human rights and build child protection capacity, and the need to further strengthen training efforts by BINUH and international partners to expand the overall capacities of the national police beyond security operations, including expanding the number of national police officers, continued vetting, enhancing community-oriented policing skills, strengthening capacity to prevent and respond to sexual and gender-based violence, ensuring the full, equal, and meaningful involvement and representation of women at all levels, ensuring respect for the rule of law, and restoring police stations that have been destroyed in gang-controlled areas,

Underscoring the need for broader efforts beyond the work of the Multinational Security Support (MSS) mission to sustainably address the root causes of gang violence, which emanate from political, institutional, and socio-economic instability and, in this regard, reiterating its call to the international community, including international financial institutions, to enhance support for long-term economic, social and institutional development in Haiti even after its stability is restored,

Underscoring the need for the international community to work with the people of Haiti in a long-term effort to promote the rebuilding of democratic institutions, including the organization of free and fair elections,

Welcoming the announcement of 29 July by the Government of Kenya to positively consider leading a multinational mission at the invitation of Haiti and in response to the appeal by the UN Secretary-General, following consultations with Haiti and the unanimous encouragement of security support to Haiti by the Security Council in resolution 2692 (2023), and further welcoming the positive responses to participate made by several Member States,

Taking note of the letter dated 26 September 2023 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council (S/2023/726), strongly expressing the desire to obtain authorization from the Security Council under

Chapter VII, and which expresses hope, following an assessment visit by a Kenyan delegation, that the Multinational Security Support mission would help ensure the security of the country's critical infrastructure and would be able to carry out targeted operations, in close collaboration with the Haitian National Police,

Recognizing the importance and urgency of curbing the illicit trafficking of arms and ammunition to Haiti to the creation of a safe operating environment for international security support, including the deployment of a multinational security support mission,

Taking note of the call made by the Government of Kenya on 21 September 2023 urging the United Nations to urgently deliver an appropriate framework to facilitate the deployment of Multinational Security Support as part of a holistic response to Haiti's challenges, calling on the Security Council to approve a resolution under Chapter VII that tailors the security support mission to the specific needs of Haiti and its people,

Determining that the situation in Haiti continues to constitute a threat to international peace and security and to stability in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

- 1. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General of their participation to form and deploy a Multinational Security Support (MSS) mission with a lead country, in close cooperation and coordination with the Government of Haiti, for an initial period of twelve months following the adoption of this resolution, to be reviewed nine months after the adoption of this resolution, on the understanding that the cost of implementing this temporary operation will be borne by voluntary contributions and support from individual Member States and regional organizations, and in strict compliance with international law, including, international human rights law, as applicable, to support the efforts of the Haitian National Police to re -establish security in Haiti and build security conditions conducive to holding free and fair elections, by:
 - (a) providing operational support to the Haitian National Police, including building its capacity through the planning and conduct of joint security support operations, as it works to counter gangs and improve security conditions in Haiti, characterized by kidnappings, sexual and gender-based violence, trafficking in persons and the smuggling of migrants and arms, homicides, extrajudicial killings, and recruitment of children by armed groups and criminal networks; and
 - (b) providing support, to the Haitian National Police, for the provision of security for critical infrastructure sites and transit locations such as the airport, ports, schools, hospitals and key intersections;
- 2. Calls on the MSS, through its support to the Haitian National Police outlined in paragraph 1, to help ensure unhindered and safe access to humanitarian aid for the population receiving assistance;
- 3. Decides that the Multinational Security Support mission, as requested by Haiti in its letter dated 22 September 2023, in coordination with the Haitian National Police, may, to prevent the loss of life and within the limits of its capacities and areas of deployment, adopt urgent temporary measures on an exceptional basis, which are limited in scope, time bound, proportionate and consistent with the objectives set forth in paragraph 1 above, to help the Haitian National Police maintain basic law and order and public safety, including through arrest and detention, as necessary and in full compliance with international law, including international human rights law, as applicable; and requests the leadership of the Multinational Security Support mission to update the Security Council any measures that may be adopted on this basis;
- 4. Calls on Member States and regional organizations to contribute personnel, equipment, and necessary financial and logistic resources based upon the urgent needs of the Multinational Security Support mission and invites contributing Member States to inform in writing the leadership of the Multinational Security Support mission, the Security Council and the Secretary-General of their intent to participate in the mission, and further requests Haiti and the leadership of the Multinational Security Support mission to update regularly the Security Council and the Secretary-General of the progress of deployment of relevant personnel and equipment;
- 5. Authorizes the Member States participating in the Multinational Security Support mission in Haiti to take all necessary measures to fulfil its mandate, strictly adhering to all international law, including international human rights law, as applicable;
- 6. Requests the Multinational Security Support mission to take fully into account child protection and the protection of other vulnerable groups as a cross- cutting issue throughout its mandate in all the planning and conduct of its operations;
- 7. Requests Member States participating in the Multinational Security Support mission in Haiti to include dedicated expertise in anti-gang operations, community-oriented policing, children and women's protection, and preventing and responding to sexual and gender-based violence in a victim-centred manner, and to take necessary action to ensure appropriate conduct and discipline and to prevent sexual exploitation and abuse, including vetting of all personnel and other safe hiring practices, encouraging women's representation at all levels of the MSS, and

predeployment and in-mission awareness training on human rights, child protection, and sexual and gender based violence, and to detect incidents when they occur and ensure a safe survivor- and victim-centred response in cases of such conduct involving their personnel, including through providing safe and accessible complaint mechanisms and timely investigations of all allegations of misconduct, to hold perpetrators accountable, and to repatriate units when there is credible evidence of misconduct, including widespread or systemic sexual exploitation and abuse, by those units;

- 8. Requests the leadership of the Multinational Security Support mission, in coordination with the government of Haiti and Member States participating in the MSS, to inform the Council, prior to the mission's full deployment, on information including but not limited to the concept of operations developed in consultations and cooperation with the government of Haiti and Member States participating in the MSS, sequencing of deployment, mission goals and end state, rules of engagement, as well as indicative financial needs to be funded by voluntary contributions, and number of personnel to be deployed;
- 9. Reaffirms that the rules of engagement and any directives on the use of force are to be developed by the leadership of the Multinational Security Support mission in consultation with Haiti and other Member States participating in the MSS and should be in full respect of Haiti's sovereignty and in strict compliance with international law, including, international human rights law, as applicable;
- 10. Requests the Member States participating in the Multinational Security Support mission in Haiti to ensure the highest standards of transparency, conduct and discipline for their contingents operating in the framework of the Multinational Security Support mission in Haiti, to establish a robust compliance mechanism to prevent, investigate, address and publicly report violations or abuses of human rights related to the Multinational Security Support mission in Haiti;
- 11. Calls on the Multinational Security Support mission to establish an oversight mechanism to prevent human rights violations or abuses, in particular sexual exploitation and abuse as well as to ensure that the planning and conduct of operations during deployment will be in accordance with applicable international law;
- 12. Requests Member States participating in the Multinational Security Support mission in Haiti to adopt appropriate wastewater management and other environmental controls to guard against the introduction and spread of water-borne diseases, in accordance with The World Health Organization Water Quality: Guidelines, Standards, and Health publication on Assessment of Risk and Risk Management for Water-related infectious diseases from 2001, and in cooperation with Haitian authorities, which bear shared responsibility for guarding against water-borne disease;
- 13. Requests the Multinational Security Support mission to cooperate with BINUH and relevant UN agencies, including but not limited to UNODC and the Office of the High Commissioner for Human Rights, to support the efforts of the Haitian National Police to re-establish security in Haiti, including efforts by the Haitian National police to combat illicit trafficking and diversion of arms and related material and to enhance management and control of borders and ports;
- 14. Decides that paragraph 11 of resolution 2653 (2022) shall be replaced by the following:
 - "Decides that, for an initial period of one year from the date of adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to Haiti, from or through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft of small arms, light weapons, and ammunition, and further decides that this measure shall not apply to:
 - a. The supply, sale, or transfer of small arms, light weapons, or ammunition to the UN or a UN-authorized mission or to a security unit that operates under the command of the Government of Haiti, intended to be used by or in coordination with those entities and intended solely to further the objectives of peace and stability in Haiti;
 - b. Other supplies, sales, or transfers of small arms, light weapons, and ammunition to Haiti as approved in advance by the Committee established pursuant to resolution 2653 (2022) to further the objectives of peace and stability in Haiti;"
- 15. Calls on all parties in Haiti to cooperate fully with the Multinational Security Support mission in the execution of its mandate and to respect the security and freedom of movement of the Multinational Security Support mission;
- 16. Requests the Secretary-General to establish a trust fund as a mechanism that can facilitate voluntary contributions to the Multinational Security Support mission to enable and operationalize the mandate;
- 17. Affirms the Secretary-General may provide logistical support packages to the MSS, when requested by the MSS and MSS donors, subject to the full financial reimbursement to the United Nations through available voluntary contributions, and in full respect of the United Nations Human Rights Due Diligence Policy (HRDDP);

- 18. Requests the leadership of the Multinational Security Support mission to ensure the highest standards of transparency and conduct, and to report every three months once the MSS is operational on the ground, as a part of regular reporting to the Security Council, through the Secretary-General, on the implementation of the resolution, including but not limited to composition of the mission, measures to ensure appropriate conduct and discipline, and to prevent sexual exploitation and abuse; and on investigations of allegations of misconduct and excessive use of force;
- 19. Requests the Secretary-General to provide as part of the Secretary-General's regular reporting to the Security Council, no later than nine months following adoption of this resolution, recommendations on possible adaptation of the mandate of the Multinational Security Support mission or its transformation as needed;
- 20. Requests the leadership of the Multinational Security Support mission to develop a strategy for mission conclusion and withdrawal and include information on that matter in regular reporting to the Security Council;
- 21. Emphasizes the need for Member States, United Nations organs, bodies and agencies, and other international organizations, including international financial institutions, to redouble their efforts to promote the institutional, social, and economic development of Haiti, in particular for the long-term, in order to achieve and sustain stability and combat poverty;
- 22. Strongly urges the Haitian authorities and other stakeholders to cooperate fully with the good offices of CARICOM and BINUH to reach compromise for the broadest possible consensus as soon as possible;
- 23. Decides to remain actively seized of the matter.